



# कार्यान्वयन-

किसी आदेश या प्रस्ताव आदि को काम के रूप में बदलने या उन पर अमल करने को कार्यान्वयन कहते हैं। कार्यान्वयन किसी भी स्तर के नियम या प्रस्ताव की राह का एक अहम पड़ाव है। उचित कार्यान्वयन पर जोर देना भारत की प्रगति के लिए एक अहम आवश्यकता है। कार्यान्वयन हमेशा से भारत की सबसे बड़ी कमजोरी रही है और नीति निर्माता काफी अरसे से हमारी जटिलता और विविधता से खुद को दिलासा देते आए हैं। भारत में शोध यही दर्शाता है कि अभी तक कोई भी सरकार अपने 'बेहतरीन तरीके से गढ़े' चुनावी घोषणापत्र को पूरी तरह लागू नहीं कर पाई। यह देखते हुए कि हमारे प्रधानमंत्री के पास भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने का सपना और दृष्टिकोण है लेकिन यहां केवल उस दृष्टि-टकोण को अमल में लाने का सवाल ही आड़े आ जाता है। असल में हमें काम को कुछ अलग ढंग से अंजाम देने की जरूरत है, जिसमें विभिन्न मंत्रालय, विभाग और अफसरशाह उचित तरीके से सामंजस्य बिठाकर काम कर सकें।



**STARTUP  
INDIA  
ROCKS! 2018**



☐ उदाहरण के तौर पर 'मेक इन इंडिया', 'कौशल भारत' और 'स्टार्टअप इंडिया' सभी सरकार के लिए खास योजनाएं हैं लेकिन कितने लोग उन्हें वास्तविक वृद्धि का सशक्त संवाहक मानते हैं? इनमें से प्रत्येक का जिम्मा अलग-अलग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्या उनके बीच कोई कड़ी है और कौन इसका जिम्मेदार है?

☐ रणनीतिक एजेंडे, मापकों, लक्ष्यों, संबद्ध कवायदों और सही नज-रिये के संतुलन की कमी से देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्य मंजिल से दूर ही रह जाएंगे।

☐ सरकार निजी क्षेत्र की साझेदारी के साथ कौशल भारत पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है लेकिन इसका कोई आकलन नहीं किया जा रहा है कि प्रत्येक मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के तहत ही कितने रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं।

☐ नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समक्ष अभी हाल में एक प्रस्तुतिकरण दिया गया कि सरकार तंत्र में एकरूपता और शासन के स्तर को सुधारने के लिए कैसे कदम उठा सकती है।

☐ किसी भी सरकार की भूमिका सामाजिक और आर्थिक मूल्यों के सृजन की होती है। ये मूल्य नेतृत्व, लोगों एवं कौशल, नवाचारी प्रक्रिया, सूचना पूंजी एवं संस्कृति जैसी अचल परिसंपत्तियों से सृजित होते हैं।



**प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना**

# एक पड़ाव

हाल के दौर में दुनियाभर में सरकारों ने अनुकरणीय कार्यान्वयन की अद्भुत मिसालें पेश की हैं। विश्व के विभिन्न शहर चमकने में सफल रहे हैं लेकिन भारत में अभी तक इसका इंतजार है, जिसके लिए सशक्त नेतृत्व की दरकार है।

## सुधार के लिए आवश्यकता

□ कार्यान्वयन के लिए नीति निर्माताओं को कई स्तरों पर समझ की जरूरत होती है। अमूमन किसी भी नीतिगत संतुलन में विरोधाभासी ताकतें समाहित होती हैं। सरकार को दीर्घावधिक प्रतिबद्धता दर्शानी चाहिए लेकिन उसे तात्कालिक राजनीतिक जरूरतों के मुताबिक भी कदम उठाने होते हैं।

□ मूल्य खास प्रक्रियाओं के जरिये ही सृजित होते हैं। अगर सरकार अपने वादे के मुताबिक नतीजे चाहती है तो उसे सही प्रक्रियाओं का चयन करना होगा।

संतुलित कार्यान्वयन एजेंडे को लागू करने में सरकार की राह में मुश्किलें आएंगी। जवाबदेही बढ़ाने और स्पष्ट दृष्टिकोण के लिए निजीकरण, राजनीतिक एजेंडे और कुछ प्रदर्शन पैमानों की बढ़ती जरूरत पर उसे अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। सफलता तभी हासिल हो पाएगी, जब विभिन्न मंत्रालयों और क्षेत्राधिकारों के बीच एकीकरण होगा, विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन स्थापित होगा, सभी अंशभागियों को साथ लेकर कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

अतः उचित कार्यान्वयन भी देश के लिए किसी चुनौती से कम नहीं किंतु अगर हम सही दिशा में काम करें तो यह अवश्य किया जा सकता है।

निकिता गुंबर

सी.एस

चतुर्थ वर्ष



एक कदम स्वच्छता की ओर



**SKILL INDIA**